



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262079
CG-DL-E-28032025-262079

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]
No. 93]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

मामला सं.-एडी(एमटीआर) 01/2024

विषय: थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉयल" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

फा. सं. 07/3/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स १४ाम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वैकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रविराज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें ८० माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल (जिसे आगे "सबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि थाईलैंड (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई सबद्ध वस्तुओं के आयात के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने की आवश्यकता की जांच की जा सके।
- चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए ८० माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल के संबंध में पाटनरोधी जांच पाटन की प्रकृति और सीमा तथा घरेलू उद्योग पर इसके क्षतिकारक प्रभाव की जांच करने के लिए २० जून २०२० को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम संख्या ६/२१/२०२०-डीजीटीआर, दिनांक १८ जून २०२१ के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या ५१/२०२१-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक १६ सितंबर २०२१ के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था।
- वर्तमान मध्यावधि समीक्षा इस नियमावली के नियम २३(१क) के साथ पठित अधिनियम की धारा ९क के अनुसार शुरू की गई थी। प्राधिकारी को किसी भी हितबद्ध पक्षकार के लिए या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करना आवश्यक है।

4. प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिसूचना की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के माध्यम से मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें सबद्ध देश से सबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई।
- ख. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करने के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए भारत में थार्फलैंड के दूतावास, सबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता संघों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भेजी।
- ग. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और थार्फलैंड सरकार को, अपने दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की, जिन्होंने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित रूप में अनुरोध किया था।
- घ. प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत करने संबंधी सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की तथा उन्हें प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित प्रारूप और तरीके से समय सीमा (विस्तारित समय सीमा सहित) के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित है, तथा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।
- ड. प्राधिकारी ने अधिसूचना की प्रतियां तथा याचिका का अगोपनीय रूपांतरण ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अग्रेषित किया।

च. थार्डलैंड सरकार से भारत में अपने दूतावास के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। जात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार थार्डलैंड के जात उत्पादकों/निर्यातकों के विवरण के साथ थार्डलैंड के दूतावास को भी भेजी गई।

छ. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, सबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

- i. थार्ड डिंग ली न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, रेयोंग, थार्डलैंड
- ii. डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, रेयोंग, थार्डलैंड
- iii. लोफटेन (थार्डलैंड) कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने अधिसूचना और प्रश्नावलियां की एक प्रति भारत में सबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित जात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अग्रेषित की तथा उनसे इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी।

- i. कैप्रिहंस इंडिया लिमिटेड
- ii. असावा इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड
- iii. एमिनेंट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
- iv. डालफो फ्लेक्सीकैप प्राइवेट लिमिटेड
- v. डालफो फ्लेक्सीकैप प्राइवेट लिमिटेड
- vi. सिल्वर फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii. रॉकडूड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- viii. नागरीका इंडकॉन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड
- ix. सुवजय इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
- x. राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
- xi. जिल पैक

झ. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 (12 महीने) है।

ज. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन-वार आयात आंकड़े वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी प्रणाली से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में सबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य की गणना करने और निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के साथ तुलना और मिलान के लिए डीजी प्रणाली के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ट. आवेदकों और उत्तर देने वाले निर्यातकों/आयातकों से आगे की सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक यह आवश्यक मानी गई।

ठ. सभी हितबद्ध पक्षकारकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उनके द्वारा दायर किए गए अनुरोध/उत्तर/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतरण सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।

ड. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में सबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और उचित लाभ के आधार पर किया गया है, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार दी गई सूचना को ध्यान में रखा गया है। ऐसी क्षति रहित कीमत इसलिए निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

ढ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के बारे में 16 अक्टूबर 2024 को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए और उन्हें अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों और जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, इस सीमा तक कि वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी जाती हैं, इस अधिसूचना में विचार किया गया है।

त. जांच के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, जो इस अधिसूचना का आधार है, की यथासम्भव सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों को यथासम्भव संगत एवं यथासम्भव सत्यापित किया।

थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी अपेक्षित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है तथा ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।

ध. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बनेगा, हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया जाएगा, जो अंतिम जांच परिणामों में संगत पाई जाएगी।

न. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, इच्छुक पक्षों को 20 मार्च 2025 को जारी किया गया था और इच्छुक पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 25 मार्च 2025 को शाम

5 बजे तक का समय दिया गया था। इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरणों पर टिप्पणियों पर, जहाँ तक प्रासंगिक पाया गया है, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में विचार किया गया है।

प. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडी = 83.21 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित था:

निम्नलिखित को छोड़कर: "18. एल्युमीनियम फॉयल, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं या कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकिंग सामग्री के साथ 80 माइक्रोन या उससे कम मोटाई (अनुमेय सहनशीलता के साथ) के साथ समर्थित हो"

- i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल।
- ii. एलु-एलु लेमिनेट
- iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टर्ड
- iv. एल्युमीनियम फॉयल कम्पोजिट
- v. 500 एमएम से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- vi. नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल
- vii. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल
- viii. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के साथ क्लैड
- ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- x. एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड
- xi. चिपकने वाला टेप
- xii. रंग लेपित एल्युमीनियम फॉयल

19. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी मानते हैं कि सबद्ध देश से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद तथा भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई जात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद के समान हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।"

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु "80 माइक्रोन से कम काएल्युमीनियम फॉयल" है।
- विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- पॉलीयूरेथेन कोटेड एल्युमीनियम फॉयल - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग के बावजूद इसे बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि कोई भी भारतीय उत्पादक इसकी आपूर्ति नहीं कर रहा है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

निम्नलिखित को छोड़कर: “7. विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में नोट किया गया है, “एल्युमीनियम फॉयल है, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, या कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकेजिंग सामग्री के साथ 80 माइक्रोन या उससे कम मोटाई (अनुमेय सहनशीलता के साथ) के साथ समर्थित है”

- i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल।
- ii. एलु एलु लैमिनेट- एए 8079 और एए 8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लैमिनेट, एक बहु-स्तरीय अपारदर्शी लैमिनेट है, जहां एल्युमीनियम फॉयल और दोनों तरफ चिपकने वाले पदार्थ के साथ प्लास्टिक फिल्म के साथ समर्थित है; कैप्सूल/टैबलेट पैकिंग में उपयोग के लिए।
- iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टर्ड- अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टर्ड एक एल्युमीनियम फॉयल है, जिसकी मोटाई 5.5 6 माइक्रोन से 7 माइक्रोन है, और जिसे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम, या ग्लास क्लॉथ, चाहे सादे या मुद्रित के साथ समर्थित किया जाता है इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूइड लाइन कवरिंग और टी बैग एप्लीकेशन।
- iv. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट- एल्युमिनियम फॉयल को क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ के साथ या पॉली एथिलीन के साथ या उसके बिना लैमिनेट किया जाता है, चाहे प्रिंट किया गया हो या नहीं। हालांकि क्राफ्ट पेपर से लेपित अथवा समर्थित एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे में है।
- v. कैपेसिटर के लिए 500 एमएम से कम चौड़ाई वाली एल्युमिनियम फॉयल-कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल 5-माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल है जिसकी चौड़ाई 500 एमएम से कम है और 99.35% शुद्धता है, जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिकल वेल्डर, मैग्नेटो, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, पावर ट्रांसमिशन उपकरण, इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल यूनिट और इसी तरह की वस्तुओं जैसे विद्युत उपकरणों में किया जाता है।

vi. नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल- नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल वह एल्युमीनियम फॉयल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।

vii. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल- एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (अक्सर पीई) होता है जो एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है, जिसका उपयोग अग्रभाग क्लैंडिंग और साइनेज में किया जाता है।

viii. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल से लिपटा- संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल एक संक्षारण प्रतिरोधी एल्युमीनियम शीट है, जिसका निर्माण एल्युमीनियम की सतह परतों से धातुकर्म रूप से उच्च-शक्ति वाले एल्युमीनियम मिश्र धातु कोर सामग्री से बंधा होता है, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम में किया जाता है; जैसे रेडिएटर, कंडेनसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल- 10.5 माइक्रोन का एल्युमीनियम फॉयल, जिसकी सतह खुरदरी होती है और चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, छिद्रित होता है; बीयर की बोतल में इस्तेमाल किया जाना है।

x. एल्युमीनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 एमपीए से अधिक, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम और इसके भागों सहित हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते हैं।

15. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार कारों के अपवर्जन अनुरोधों पर विचार किया। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अपवर्जनों के लिए अनुरोध किया है और प्राधिकारी ने नीचे दिए गए सभी अपवर्जन अनुरोधों की जांच की है:

- बैटरी फॉइल
- 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमिनियम फॉइल
- हाउस फॉइल और एसआरसी फॉइल
- चिपकने वाला टेप
- रंग लेपित एल्युमिनियम फॉइल

i. बैटरी फॉइल- बैटरी फॉइल के अपवर्जन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि बैटरी फॉइल एक विशेष प्रकार की फॉइल है और घरेलू उद्योग वांछित विनिर्देश में बैटरी फॉइल का निर्माण करने में असमर्थ है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने बैटरी फॉइल के उत्पादन और बिक्री को दिखाने के लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। हिंडाल्को ने अनुरोध किया है कि इसकी बैटरी फॉइल का परीक्षण किया गया है और फॉइल प्रदर्शन के उच्चतम मानकों के अनुसार योग्य पाया गया है। हिंडाल्को भारत में एल्युमिनियम बैटरी फॉइल का निर्माण कर रही है और ईवी/विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए एलआईबी विनिर्माण क्रांति में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है।

एक उत्पादक/निर्यातक जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को सबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों के लिए बैटरी फॉइल को बाहर रखने की मांग की है। उत्पादक इस बात से सहमत है कि वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान भारत में ऐसी बैटरी फॉइल की कोई मांग नहीं थी। घरेलू उद्योग ने ऐसी बैटरी फॉइल की बिक्री के बीजकं बीएचईएल को प्रस्तुत किए हैं, जिनका उपयोग उच्चतर तकनीकी सीमा वाले अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में किया गया था। इस मांग के मामले में उत्पाद के विनिर्माण के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को स्थापित करता है। इसलिए, प्राधिकारी ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखते हैं।

ii. 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल- 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल को बाहर रखने के संबंध में, यह देखा गया है कि जिंदल इंडिया ने 2019 से 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमिनियम फॉयल का निर्माण शुरू किया था और उन्होंने दिसंबर 2019 में अपनी पहली वाणिज्यिक मात्रा बेची थी। जिंदल ने जांच की अवधि के दौरान बेची गई कुल वाणिज्यिक मात्रा को दर्शाते हुए विभिन्न बीजक भी प्रस्तुत

किए हैं। इस तथ्य के संबंध में कि हिंडाल्को और रविराज 5.5 माइक्रोन से कम के यूएलजी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, यह देखा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक को प्रत्येक प्रकार के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति करनी चाहिए। वास्तव में, ऐसी स्थिति में जहां बड़ी संख्या में उत्पादक एक उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उत्पाद प्रकार हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रत्येक उत्पादक कुछ उत्पाद प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करता है और कोई भी उत्पादक उत्पाद शृंखला की संपूर्णता का उत्पादन नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार, जहां घरेलू उद्योग पहले से ही एक प्रकार के संबद्ध सामान का निर्माण कर रहा है, उसे जांच के तहत उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल को बाहर करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

iii. एसआरसी और हाउस फॉयल - एसआरसी और हाउस फॉयल को बाहर रखने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ये उत्पाद प्रकार भारत में आयात किए जाते हैं और घरेलू उद्योग इन उत्पाद प्रकारों के समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। वास्तव में, एसआरसी और हाउस फॉयल का निर्माण सभी तीन याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने इसे प्रमाणित करने के लिए बीजक प्रस्तुत किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इन दो प्रकार की फॉयल को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने के औचित्य के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं दिया है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग इन प्रकारों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है और इन प्रकारों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, इसलिए इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यह देखा गया है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग इन प्रकार की सबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और घरेलू बाजार में बिक्री नहीं कर रहा है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग इन प्रकार की एल्युमीनियम फॉयल का उत्पादन करने और घरेलू बाजार में इन प्रकारों

की आपूर्ति करने में सक्षम है। इसके अलावा, किसी भी मामले में, यह नोट किया जाता है कि इस तरह के उत्पाद प्रकार का उत्पादन और आपूर्ति एक से अधिक उत्पादकों द्वारा की जाती है। संभावित मांग आपूर्ति अंतर के कारण किसी विशेष उत्पाद प्रकार को बाहर करना उचित नहीं है।

iv. एल्युमिनियम फॉयल चिपकने वाला टेप- चिपकने वाले टेप को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वे इस प्रकार का उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन वर्तमान में इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान में चिपकने वाले टेप का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और जांच अवधि में भी इसका कोई उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। प्रकटन विवरण जारी करने के बाद, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चिपकने वाले टेप को उचित रूप से पुनः परिभाषित किया जाए। तदनुसार, चिपकने वाले टेप को "चिपकने वाला टेप एल्युमिनियम फॉयल (<80 माइक्रोमीटर) एक तरफ या दोनों तरफ चिपकने वाले पदार्थ से लेपित टेप के रूप में उपयोग के लिए" के रूप में परिभाषित किया गया है।

v. रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल- रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल को बाहर रखने के संबंध में, इसे पिछली जांच में इस आधार पर बाहर रखा गया था कि घरेलू उद्योग इसका निर्माण नहीं कर रहा है। चूंकि तथ्य वर्तमान जांच के लिए भी समान हैं, इसलिए रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल को "पीवीडीएफ (फ्लोरीन कार्बन) या पीई (पॉलिएस्टर) कोटिंग के साथ एल्युमिनियम फॉयल, सीटीएच 7607 के अंतर्गत आने वाली कोटिंग" के रूप में परिभाषित किया गया है।

18. पूर्वकृत पैरा 7 और 15 को देखते हुए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद का दायरा पैरा 7 और 15 के साथ पढ़ने पर निम्नानुसार है:

निम्नलिखित को छोड़कर: "80 माइक्रोन और उससे कम मोटाई (अनुमेय सहनशीलता के साथ) के कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकिंग सामग्री के साथ मुद्रित या समर्थित एल्युमीनियम फॉयल"

- i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल।
- ii. एलु-एलु लेमिनेट
- iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टर्ड
- iv. एल्युमीनियम फॉयल कम्पोजिट
- v. 500 एमएम से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- vi. नवकाशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फॉयल
- vii. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल
- viii. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल के साथ क्लैड
- ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- x. एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड
- xi. चिपकने वाला टेप
- xii. रंग लेपित एल्युमीनियम फॉयल

10. प्राधिकारी द्वारा 18 जून 2021 को जारी अधिसूचना संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित अपवादों के साथ "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉयल" पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर 2021 के अनुसार यह शुल्क लगाया गया था।

11. प्राधिकारी चीन जन.गण. से 80 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉयल के आयात पर समानांतर जांच कर रहे हैं, जिसमें अधिसूचना संख्या 06/35/2023 दिनांक 28 अगस्त 2024 के माध्यम से अंतरिम शुल्क की सिफारिश की गई है। प्राधिकारी ने 1

जनवरी 2025 और 11 फरवरी 2025 को शुद्धिपत्र जारी किया। प्रकटन विवरण 12 मार्च 2025 को जारी किया गया है। उक्त जांच केवल चीन जन.गण. को कवर करती है और ऐसे उत्पाद के संबंध में है जो वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं, जबकि वर्तमान समीक्षा जांच केवल थाईलैंड से संबंधित है।

12. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सबदृध वस्तुओं का आयात भारत में निम्नलिखित कोडों 76071 190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत हो रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
13. प्राधिकारी ने पूर्व में की गई जांच में पीसीएन का प्रयोग किया था तथा वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भी उसी का अनुसरण किया जा रहा है।
14. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा थाईलैंड से निर्यात की गई वस्तु में कोई अधिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और थाईलैंड से आयातित वस्तुएँ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और सबदृध वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। सबदृध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता सबदृध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनों से, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ थाईलैंड से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तुएँ हैं।
- घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति
- घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार
15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

16. आवेदकों ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. यह आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वैकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ii. अन्य घरेलू उत्पादकों नामतः ईएसएस डीईई एल्युमिनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड और ट्रेफोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने दायर आवेदन पर अपने समर्थन की सूचना दी है।
- iii. आवेदक कंपनियों ने न तो सबदृध देश से सबदृध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक या सबदृध देश के उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं।
- iv. आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक 'बड़ा हिस्सा' है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके

आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

18. यह आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स ९याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रविराज फोइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फोइल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने न तो सबद्ध देश से सबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे सबद्ध देश से सबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार, यह आवेदन पाटनरोधी शुल्क नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

उ. मध्यावधि समीक्षा का दायरा और बदली हुई परिस्थितियां

उ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. वर्तमान समीक्षा के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत नियम 23(1क) के प्रावधानों के विपरीत है और अनावश्यक है। पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने के लिए एमटीआर शुरू नहीं की जा सकती। नियम 23(1क) के प्रावधानों में कहा गया है कि एमटीआर केवल शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए शुरू की जा सकती है।
- पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की पुनः जांच किए बिना वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- प्राधिकारी शुल्क को पूर्ण या आंशिक रूप से वापस लेने की सिफारिश केवल तभी कर सकते हैं, जब यह देखा जाता हो कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने की संभावना नहीं है। पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता की

जांच करने के लिए एमटीआर शुरू करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

- iv. घरेलू उद्योग को पता होना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि का अनुरोध करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा नियम 23(1क) के तहत मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसने अवशोषणरोधी समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया।
- v. एमटीआर अनावश्यक है क्योंकि मूल पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद से काफी समय बीत चुका है। समय-सीमा पर विचार करते हुए, यह अल्पकालिक होगा और केवल लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। मूल पाटनरोधी शुल्क सितंबर, 2026 में समाप्त होने वाला है।
- vi. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि उत्पाद प्रकारों के कारण वर्तमान जांच की अवधि में भारत को निर्यात की उत्पाद प्रोफाइल बदल गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कैसे प्राप्त किया गया है और यदि सही भी है, तो जांच की अवधि में शायद ही कोई बदलाव हुआ है।
- vii. नियम 23(1क) के तहत एमटीआर की गारंटी देने वाली याचिका में कोई सकारात्मक सूचना नहीं है। इस बात का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है कि थाई उत्पादकों ने लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी निर्यात कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. समीक्षा के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. थाईलैंड में निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- ii. पिछली जाँच और वर्तमान जाँच के बीच निर्यातकों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद प्रोफाइल में बदलाव आया है।
- iii. कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है जो निर्यात कीमत में परिलक्षित नहीं होती है।

- iv. निर्यात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बिना सामान्य मूल्य में परिवर्तन के कारण पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है।
- v. एनआईपी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन में भी वृद्धि हुई है।
- vi. बदली हुई परिस्थितियाँ समीक्षा की मांग करती हैं क्योंकि उत्पाद प्रोफाइल में बदलाव हुआ है। उच्चतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वाले उत्पादों के आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में कुल आयातों की तुलना में भी वृद्धि हुई है।
- vii. आयातों की पहुँच कीमतों में बदलाव हुआ है। कच्चे माल की कीमतों और लागतों में वृद्धि हुई है। निर्यात कीमत में भी वृद्धि हुई है। पीसीएन स्तर पर देखा जाए तो निर्यात कीमत में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जितनी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। इनपुट लागत में वृद्धि के कारण एनआईपी में भी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में आयात में भी काफी वृद्धि हुई है।
- viii. कानून के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से और सीधे तौर से कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध करने पर समीक्षा शुरू कर सकते हैं। प्रतिवादी ने नियम 23 के केवल उप-नियम (1क) का चयनित पाठन इसके अन्य प्रावधानों का संदर्भ लिए बिना किया है। प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्राधिकारी शुल्क वापस लेने या इसे नीचे की ओर संशोधित करने तक ही सीमित नहीं है। प्राधिकारी को मध्यावधि समीक्षा में शुल्क बढ़ाने का अधिकार है।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात की उपेक्षा की है कि प्रावधान प्राधिकारी को किसी भी "हितबद्ध पक्षकार" के अनुरोध पर समीक्षा शुरू करने की अनुमति देता है, जिसमें नियम 2(ग) के अनुसार भारत में समान वस्तु का उत्पादक भी शामिल है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा मध्यावधि समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन समर्थन किए जाने योग्य है।

- x. नियम 23(1क) को सरलता से पढ़ने से यह नहीं लगता कि प्राधिकारी केवल शुल्क वापस लेने या इसे नीचे की ओर संशोधित करने तक ही सीमित है।
- xi. नियम 23(1क) में यह अधिदेश दिया गया है कि प्राधिकारी को किसी भी हितबद्ध पक्षकार से अनुरोध पर समीक्षा आरंभ करनी चाहिए जो आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सूचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह पुष्टि करता है कि यदि मध्यावधि समीक्षा में यह निर्धारित होता है कि शुल्क लगाने की कोई और आवश्यकता नहीं है तो प्राधिकारी पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर सकते हैं।
- xii. शब्द "भिन्न", जो प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क को संशोधित करने की अनुमति देता है, यह सुझाव देने तक सीमित नहीं है कि इसे केवल नीचे की ओर ही भिन्न हो सकता है।
- xiii. घरेलू उद्योग का दावा है कि उप-नियम (1क) के दायरे को समझाने के लिए नियम 23 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और उप-नियम (1) और (3) उप-नियम (1क) के अनुप्रयोग की सूचना देते हैं।
- xiv. नियम 23(1) पाटनरोधी समीक्षा के लिए सामान्य सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि पाटनरोधी शुल्क तब तक लागू रहते हैं जब तक क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो। "आवश्यक सीमातक" वाक्यांश नियम 23(1क) और (1ख) के तहत समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी की शक्ति को स्वीकार करता है। नियम 23(1) पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 के साथ संरेखित है।
- xv. यूएस-डीआरएएमएस की पैनल रिपोर्ट में, पैनल ने देखा कि अनुच्छेद 11.1 में एक सामान्य आवश्यकता की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहते हैं जब तक क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 11.2 इस नियम के अनुप्रयोग को निर्दिष्ट करता है, जिससे प्राधिकारियों को शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

xvi. ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग्स में पैनल ने नोट किया कि अनुच्छेद 11.1 यह अधिदेश देता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तभी लागू रहते हैं जब क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो। यह सामान्य, स्पष्ट आवश्यकता अनुच्छेद 11.2 और 11.3 में समीक्षा प्रक्रियाओं का आधार बनती हैं।

xvii. यूएस - श्रिम्प II (वियतनाम) में पैनल ने दोहराया कि अनुच्छेद 11.2 और 11.3 अनुच्छेद 11.1 की सामान्य आवश्यकता की जरूरत को लागू करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 11.2 व्यक्तिगत उत्पादकों/निर्यातकों पर लगाए गए शुल्कों की सीमा और अवधि पर ध्यान देता है, जबकि अनुच्छेद 11.3 किसी अन्य सदस्य से पूरे आयात पर उपाय लगाने से संबंधित है।

xviii. पाकिस्तान - बीओपीपी फिल्म (यूएई) में, पैनल ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 11.1 यह प्रावधान करता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहते हैं जब तक क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 11.1 एक व्यापक सिद्धांत स्थापित करता है, जो अनुच्छेद 11 के बाकी हिस्सों में बदली हुई परिस्थितियों और निर्णायक समीक्षाओं के लिए प्रक्रियाओं में लागू होता है।

xix. अनुच्छेद 11.2, अनुच्छेद 11.1 के सिद्धांतों को लागू करता है, जो यह अनिवार्य करता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक ही लागू रहेगा, जब तक क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो, और समीक्षा के दौरान शुल्कों में संशोधन हो सकता है।

xx. नियम 23(1क) अनुच्छेद 11.2 के तहत भारत के दायित्वों के समान है और इसकी व्याख्या इसी तरह की जानी चाहिए। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बैंगलोर बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संधि दायित्वों के साथ संरेखित संविधियों की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि हस्ताक्षरकर्ता देशों में समान रूप से लागू हो सके।

xxi. नियम 23(1क) का प्रयोग नियम 23(1) के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने को अधिकृत करते हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार शुल्क अलग अलग है जिसके फलस्वरूप संभावित रूप से उच्चतर शुल्क लगेगा।

xxii. नियम 23(3) नियम 10 और 17 के प्रावधानों को नियम 23(1क) के तहत मध्यावधि समीक्षा पर लागू करता है, जिससे प्राधिकारी को अनुबंध III में सिद्धांतों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक शुल्कों की सिफारिश करने की अनुमति मिलती है।

xxiii. फेयरडील पॉलीकेम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 23(3) में "यथोचित परिवर्तनों" के आधार पर, नियम 17(1) आवश्यक परिवर्तनों के साथ समीक्षाओं पर लागू होता है, जो छह महीने के अनुमेय विस्तार को बढ़ाता है।

xxiv. चूंकि नियम 17 के प्रावधान जांच पर लागू होते हैं, इसलिए प्राधिकारी क्षतिकारक पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक शुल्कों की सिफारिश करते हुए निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन के मार्जिन का निर्धारण कर सकते हैं,

xxv. यह प्रश्न कि क्या प्राधिकारी मध्यावधि समीक्षा में शुल्कों को बढ़ा सकते हैं, सेस्टैट द्वारा गौर एंड वेइल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में इस पर ध्यान दिया गया है, जहां इसने घरेलू उद्योग द्वारा मध्यावधि समीक्षा आवेदन के बाद शुल्कों में वृद्धि को बरकरार रखा।

xxvi. प्रतिवादी का तर्क है कि नियम 23(1क) स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि घरेलू उत्पादक ईयू पाटनरोधी नियमावली के विपरीत बढ़ी हुई पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन कर सकता है।

xxvii. घरेलू उद्योग का तर्क है कि चूंकि नियम 23(1) और नियम 23(3) नियम 23(1 क) को नियंत्रित करते हैं, इसलिए मध्यावधि समीक्षा में शुल्क बढ़ाने की शक्ति की पुष्टि के लिए किसी अतिरिक्त स्पष्ट कथन की आवश्यकता नहीं है।

xxviii. पिछली तर्कों में, यह दावा किया गया था कि नियम 23 और धारा 9क(5) प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं, जो शुल्कों के विस्तार की अनुमति देते हैं यदि समाप्ति से पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

xxix. स्पष्ट भाषा न होने के बावजूद, थाई ऐक्रेलिक फाइबर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट ने माना कि प्राधिकारी के पास पाटन के खिलाफ उन्हें प्रभावी बनाने के लिए शुल्क बढ़ाने की आकस्मिक और सहायक शक्तियां हैं।

xxx. शंघाई फॉर्च्यून केमिकल्स कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में भी इसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा गया था, जहां सेस्टैट ने नोट किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए समीक्षा के दौरान उच्चतर या निम्नतर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं।

xxxi. यह गलत तर्क दिया गया है कि अवशोषण-रोधी जांच के लिए विशिष्ट प्रावधानों के कारण प्राधिकारी नियम 23(1क) के तहत मध्यावधि समीक्षा शुरू नहीं कर सकते थे।

xxxii. घरेलू उद्योग का तर्क है कि एक अलग अवशोषण-रोधी जांच का प्रावधान नियम 23(1क) के तहत मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के प्राधिकारी की शक्ति को सीमित नहीं करता है, बशर्ते कि आवश्यकताएं पूरी हो गई हों और एक प्रमाणित आवेदन दायर किया गया हो।

xxxiii. घरेलू उद्योग आगे तर्क देते हैं कि ऋषिरूप पॉलिमर्स के फैसले पर डिंगेंग का विश्वास चयनात्मक पठन पर आधारित है और दावा करता है कि उच्चतम न्यायालय विशिष्ट मापदंडों की जांच करने के प्राधिकारी के कर्तव्य को मान्यता देता है।

xxxiv. डीजीटीआर की पिछली और वर्तमान कार्य-पद्धतियां शुल्कों को संशोधित करने और बढ़ाने के लिए मध्यावधि समीक्षा के संचालन का समर्थन करती हैं, जैसा कि विभिन्न जांचों में कई अंतिम जांच परिणामों से स्पष्ट होता है।

xxxv. विभिन्न मामले घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति का मुकाबला करने के लिए पाटनरोधी शुल्कों में संशोधन और निरंतरता की सिफारिश करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

xxxvi. प्राधिकारी द्वारा अवशोषण-रोधी समीक्षा आरंभ न करके इसके स्थान पर मध्यावधि समीक्षा आरंभ करने का निर्णय यह प्रमाणित करता है कि प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा को उपयुक्त कार्रवाई माना है।

xxxvii. दायर किया गया आवेदन सकारात्मक सूचना तथा उचित समयावधि बीतने के कानून द्वारा अपेक्षित दोनों मानदंडों को पूरा करता है।

xxxviii. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के माध्यम से पीसीएन-वार आंकड़े प्राप्त किए।

xxxix. शुल्क लगाए जाने के पश्चात निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद प्रोफाइल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

xl. मूल जांच में लागू पाटन और क्षति मार्जिन की सीमा विभिन्न पीसीएन के विभिन्न हिस्से के आधार पर थी। वर्तमान जांच में उच्च लागत वाले पीसीएन की आयात मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पाद प्रोफाइल में परिवर्तन भारित औसत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि विभिन्न पीसीएन में पाटन और क्षति की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. वर्तमान जांच नियम 23(1क) के अनुसार शुरू की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, वहां किसी भी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा स्वयं पहल पर या किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर करेगा, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से उचित समय बीत चुका है और ऐसी समीक्षा के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेगा, जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या फिर से होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है और इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है।”

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान समीक्षा घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर शुरू की गई है। वर्तमान जांच इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है जो पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि को उचित ठहराता है। अपने आवेदन में, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:

- क. निर्यातक द्वारा भारतीय बाजार में निर्यात किए जाने वाले उत्पाद प्रोफाइल में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
- ख. निर्यात कीमत में आनुपातिक वृद्धि के बिना कच्चे माल की कीमत और परिणामस्वरूप लागत में अधिक वृद्धि हुई है।
- ग. भारतीय उद्योग के उत्पादन प्रोफाइल में अधिक बदलाव हुआ है।

क. विदेशी उत्पादकों के उत्पाद प्रोफाइल में बदलाव

23. नीचे दी गई तालिका आयातों के उत्पाद प्रोफाइल में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न पीसीएन के लिए आयात के पैटर्न में मूल जांच की तुलना में कुछ परिवर्तन आया है। तथापि, मूल जांच और एमटीआर की जांच अवधि दोनों में 80% निर्यात तीन उत्पाद प्रकारों हाउस फॉयल बेयर, एसआरसी बेयर और यूएलजी बेयर में संकेतित हैं। इस प्रकार, जबकि परिवर्तन है, इसे प्रकृति में महत्वपूर्ण और संरचनात्मक नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न उत्पाद प्रकारों के निर्यात या बिक्री से जांच की अवधि के दौरान प्रचलित शेयरों को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा करना कठिन हो सकता है। चूंकि बाजार की ताकतें गतिशील प्रकृति के हैं, इसलिए कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं और उन्हें अनुमति देने की आवश्यकता है। यदि ऐसे वास्तविक परिवर्तन हैं जो स्थायी प्रकृति के हैं तो यह आने वाला नहीं है। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि उत्पाद प्रोफाइल में परिवर्तन न तो अधिक हैं और न ही स्थायी प्रकृति के साबित हुए हैं।

फॉइल का प्रकार	मूल जांच के अनुसार आयात मात्रा	वर्तमान जांच के अनुसार आयात	हिस्सा	
			एमटी	एमटी
			%	%
एलू एलू स्टॉक बेयर	83	1,860	0.50%	7.79%

हाउस फ़ॉइल बेयर	3,900	5,364	23.31%	22.46%
एलजी बेयर	1,401	2,525	8.37%	10.57%
एलजी कन्वर्टड	18	25	0.11%	0.10%
एमजी बेयर	617	409	3.69%	1.71%
एमजी कन्वर्टड	1,184	8	7.08%	0.03%
एसआरसी बेयर	5,761	4,338	34.43%	18.17%
यूएलजी बेयर	3,767	9,352	22.52%	39.16%
हाउस फ़ॉइल कन्वर्टड	-	0	0.00%	0.00%
कुल योग	16,731	23,882	100.00%	100.00%

ख. कच्चे माल की लागत में बहुत अधिक वृद्धि

24. इस अनुरोध के संबंध में कि कच्चे माल की कीमतों और लागतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात कीमत में वृद्धि होनी चाहिए, प्राधिकारी ने मूल जांच की अवधि और वर्तमान जांच की अवधि में यथा-लागू इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। नीचे दी गई तालिका ऐसी तुलना दर्शाती है।

विवरण (भारित औसत)	यूनिट	मूल जांच की अवधि	वर्तमान जांच की अवधि	वृद्धि
कच्चे माल की लागत	रु./एमटी	***	***	***
एनआईपी	रु.	***	***	***

25. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत कच्चे माल की लागत में *** रुपये की वृद्धि हुई है तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -III के अनुसार क्षति रहित कीमत में *** रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि के लिए प्रमुख लागत कच्चे माल की लागत में परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

26. इसके अलावा मूल जांच की अवधि और एमटीआर जांच की अवधि के बीच आयात कीमत के संदर्भ में भिन्नता नीचे दी गई तालिका से देखी जा सकती है:-

फॉइल का प्रकार	आयात कीमत रु./एमटी		
	ओ.आई	एमटीआर	परिवर्तन
एलू एलू स्टॉक बेयर	2,15,506	3,25,854	1,10,348
होम फँइल बेयर	1,96,114	2,81,233	85,120
लाइट गेज (एलजी) बेयर	2,28,707	3,25,382	96,674
मीडियम गेज (एमजी) बेयर	1,95,838	3,56,246	1,60,408
मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टर्ड	2,44,815	10,26,227	7,81,412
सेमी रिगिड कंटेनर (एसआरसी) बेयर	1,98,754	2,94,261	95,507
अल्ट्रा लाइट गेज बेयर	2,27,301	3,61,066	1,33,765
भारित औसत			1,10,946

27. जैसा कि आयात कीमत से संबंधित तालिका से स्पष्ट है, भारित औसत अंतर *** रुपये/एमटी है। तुलना से यह स्पष्ट है कि आयात कीमत और एनआईपी में वृद्धि लगभग समान है। इस प्रकार आयात कीमत और एनआईपी मोटे तौर पर एक साथ बढ़े हैं। परिस्थितियों में वास्तविक परिवर्तन एनआईपी और आयात कीमत के बीच परस्पर परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है।

ग. भारतीय उद्योग के उत्पादन प्रोफाइल में बहुत अधिक बदलाव

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच की अवधि की तुलना में एमटीआर जांच अवधि में भारतीय उद्योग के उत्पादन की संरचना में कुछ हद तक बदलाव आया है। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे विभिन्न उत्पाद प्रकारों के हिस्से में भिन्नता को उजागर करती है। विशेष रूप से, अलू अलू बेयर स्टॉक और अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर में घरेलू उद्योग के उत्पादन हिस्से में वृद्धि हुई है। यदि इसकी तुलना पैरा 24 में तालिका में आयात संरचना से की जाए, तो वही प्रवृत्ति दिखाई देती है। इन दो उत्पाद प्रकारों में आयात में भी काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के उत्पादन और आयात दोनों ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं।

फॉयल का प्रकार	कुल		हिस्सा	
	ओ.आई	एमटीआर	ओ.आई	एमटीआर
एलू एलू स्टॉक बेयर	***	***	***	***
होम फँइल बेयर	***	***	***	***
लाइट गेज (एलजी) बेयर	***	***	***	***
लाइट गेज (एलजी) कन्वर्टड	***	***	***	***
मीडियम गेज (एमजी) बेयर	***	***	***	***
मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टड	***	***	***	***
सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी) बेयर	***	***	***	***
अल्ट्रा-लाइट गेज नंबेयर	***	***	***	***
हाउस फँइल कन्वर्टड	***	***	***	***
सिगरेट फँइल	***	***	***	***
सेमी रिगिड कंटेनर (एसआरसी) कन्वर्टड	***	***	***	***
कैपेसिटर फँइल	***	***	***	***
कुल	***	***	***	***

29. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक को परिस्थितियों में इस सीमा तक परिवर्तन सिद्ध करना अपेक्षित है कि जिस आधार पर शुल्क लगाया गया था, वह वास्तविक रूप से इतना बदल गया है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आलोक में, तथा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना और सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच के दौरान स्थापित तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में पहचाने गए आधार मौजूद नहीं हैं।

च. प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ

च.1 अन्य इच्छुक पक्षों के विचार

30. प्राधिकरण द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं :

- i. यह बहुत स्पष्ट है कि आवेदक नियम 23(1ए) के तहत थार्डलैंड से विषयगत वस्तुओं के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क की समीक्षा को उचित ठहराने के लिए कोई सकारात्मक जानकारी रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान जांच को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
- ii. प्रकटीकरण विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक ऐसे किसी भी आधार के अस्तित्व को इस हद तक प्रदर्शित नहीं कर सके कि मौजूदा ADD की समीक्षा की आवश्यकता हो।
- iii. प्रकटीकरण के पैरा 23 से पता चलता है कि भारत के निर्यातकों के उत्पाद प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। विचार किए गए 9 पीसीएन में से, यूएलजी बेयर और एलू एलू स्टॉक बेयर के आयात में कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन दो पीसीएन में ऐसी वृद्धि यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उत्पाद प्रोफाइल में ही कोई बदलाव हुआ है जिससे मौजूदा एडीडी की प्रभावशीलता पर असर पड़े।
- iv. आयात मूल्य और एनआईपी मोटे तौर पर एक साथ चले हैं। यह अवलोकन इस तर्क को गलत साबित करता है कि कच्चे माल के कारण लागत में वृद्धि हुई है जो निर्यात मूल्य में वृद्धि में आनुपातिक रूप से परिलक्षित नहीं होती है। किसी भी मामले में, हमारे द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- v. अलू स्टॉक बेयर की मात्रा में वृद्धि घरेलू उद्योग जैसे आयात के लिए भी दिखाई दी है, जो दर्शाता है कि इन उत्पाद प्रकारों की मांग में वृद्धि हुई है, जिसे इन उत्पादों की खपत में एक प्राकृतिक विकास के रूप में माना जाना चाहिए और कथित रूप से किसी भी उत्पाद बदलाव का परिणाम नहीं माना जाना चाहिए।
- vi. वर्तमान एमटीआर का मूल आधार निराधार है, इस समीक्षा में डंपिंग और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है और डंपिंग और क्षति मार्जिन का कोई नया मूल्यांकन न करने के लिए यह खुलासा उपयुक्त है।
- vii. जैसा कि तथ्य उजागर हुए हैं, यह निष्कर्ष निकालना उचित और न्यायसंगत है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में पहचाने गए आधार मौजूद नहीं हैं।
- viii. प्रत्यर्थी प्राधिकरण की टिप्पणियों से सहमत है तथा प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वे ऐसी टिप्पणियों की पुष्टि करें तथा फलस्वरूप वर्तमान जांच को समाप्त करें।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

31. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:

- i. कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से डीआई की लागत में वृद्धि हुई, जिससे गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) में वृद्धि हुई। एनआईपी में वृद्धि निर्यात मूल्य (ईपी) की तुलना में बहुत अधिक है और इस संबंध में प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।
- ii. प्राधिकरण ने पाया कि एनआईपी और आयात मूल्य में वृद्धि लगभग समान है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। आवेदक ने इस पर विवाद किया है और आगे और दलीलें दी हैं।
- iii. प्राधिकरण ने पाया कि भारतीय उद्योग के उत्पादन की संरचना में बदलाव आया है, घरेलू उद्योग के अलू अलू बेयर स्टॉक और अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर का उत्पादन बढ़ रहा है। उक्त उत्पाद के आयात में भी वृद्धि हुई है।
- iv. आवेदक ने बाजार खुफिया जानकारी के आधार पर डीआई द्वारा निर्धारित डीएम और आईएम प्रदान किया है, जिसमें एनआईपी और सीएनवी शामिल हैं। मौजूदा एडीडी के साथ डीएम और आईएम की तुलना करने पर स्पष्ट रूप से संबंधित मार्जिन में पर्याप्त वृद्धि दिखाई देती है। इस प्रकार, परिस्थितियों में परिवर्तन स्पष्ट है और यह अवलोकन विवादित है कि एनआईपी और ईपी समान स्तर पर बढ़े हैं। यदि ऐसा होता, तो डीएम और आईएम में इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती।
- v. भारित औसत एनआईपी में वृद्धि *** रुपये/एमटी है जबकि भारित औसत आयात मूल्य में वृद्धि *** रुपये/एमटी है।
- vi. ई.पी. में गिरावट या ई.पी. में वृद्धि, लागत में वृद्धि की तुलना में अनुपातहीन रूप से कम होने के बावजूद, यदि प्राधिकरण अपने प्रस्तावित निष्कर्ष पर कायम रहता है, तो यह 'परिवर्तित परिस्थितियों' की अवहेलना होगी तथा कानून को निष्फल बना देगा।
- vii. वर्तमान मामले में आवेदन प्रपत्र में परिवर्तन की स्थिति के लिए पहचाने गए मापदंडों के अनुसार कार्रवाई योग्य कारक होने के बावजूद, प्रस्तावित निष्कर्ष में उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है।
- viii. उद्योग प्रोफाइल में पेटेंट परिवर्तन हुआ है। मूल जांच के दौरान, यह 16 उत्पादकों से बना था, उत्पाद प्रोफाइल में परिवर्तन के साथ उत्पादकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

- ix. यह देखा जा सकता है कि जब चार उत्पाद कुल बाजार का लगभग ***% हिस्सा बनाते हैं, तब भी चार उत्पादों की संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। जहाँ पहले मीडियम गेज उत्पाद बहुसंख्यक थे, वहीं अब अल्ट्रा-लाइट गेज उत्पाद बहुसंख्यक हैं।
- x. अल्ट्रा-लाइट गेज में उल्लेखनीय मांग रही है तथा एलएसकेबी, जीएलएस, एसएसपीएल और एसवीईएल ने संयंत्र स्थापित कर मुख्य रूप से इसी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है।
- xi. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, आयात मूल्य में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।
- xii. प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर आवेदन स्वीकार किया था। जांच के दौरान तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रमाणित करने के लिए घरेलू उद्योग को कोई अवसर नहीं दिया गया।
- xiii. थाईलैंड से आयात में वृद्धि दर; थाई आयात के आयात मूल्य में गिरावट; तीसरे देशों द्वारा धोखाधड़ी, ये सभी परिवर्तन की स्थायी प्रकृति को प्रमाणित करते हैं।
- xiv. दायर ईक्यूआर के विश्लेषण से यह भी प्रमाणित होता है कि वे अधिशेष क्षमता के साथ निर्यातोन्मुख हैं तथा उनके निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है।
- xv. थाईलैंड से आयात में वृद्धि हुई, जबकि बाद में इसमें गिरावट आई। ऐसा चीन जनवादी गणराज्य पर शुल्क समाप्त होने के कारण हुआ। घरेलू उद्योग में भारतीय मांग को पूरी तरह से पूरा करने की क्षमता है।
- xvi. पीसीएन के अनुसार आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी नीचे रही हैं। जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई जबकि बिक्री लागत में वृद्धि हुई। इस प्रकार, महत्वपूर्ण मंदी है।
- xvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी कम है और इससे अवैध डंपिंग का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकेगा।
- xviii. मानकीकरण अनुचित है क्योंकि विषयगत वस्तुओं में विभिन्न पीसीएन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को उत्पाद की मोटाई के आधार पर अलग-अलग कच्चे माल की खपत, उपयोगिता उपयोग और क्षमता उपयोग की आवश्यकता होती है।
- xix. वास्तविक आधार पर रिपोर्ट की गई जीएलएस की उपयोगिता लागतों पर विचार न करना, तथा इसके बजाय उपयोगिता लागतों की गणना के लिए रवि राज यूनिट ॥ के उपभोग कारकों का उपयोग करना न केवल नियमों के साथ असंगत

है, बल्कि इससे किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक की तुलना में उपयोगिता लागत कम हो गई है।

- xx. प्राधिकरण ने कच्चे माल की लागत का मानकीकरण करते समय गलती से WIP में परिवर्तन को शामिल कर लिया है, हालांकि क्षति अवधि के दौरान WIP सकारात्मक और नकारात्मक आंकड़ों के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है, तथा बाद वाले को अभी भी मानकीकरण के लिए शामिल किया गया है।
- xxi. प्राधिकरण ने विपणन व्यय और शाखा/मुख्यालय व्यय सहित अप्रत्यक्ष बिक्री और वितरण व्यय को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया है। यह नियमों के अनुसार नहीं है और इसे पहले कभी भी अस्वीकृत नहीं किया गया है।
- xxii. रविराज के लिए उत्पादन लागत को पिछले क्षमता उपयोग पर विचार करके गलत तरीके से मानकीकृत किया गया है, जबकि क्षमता उपयोग में गिरावट संबंधित उत्पाद और उसकी जरूरतों के कारण है। क्षमता उपयोग में गिरावट उत्पादन क्षमता का अकुशल उपयोग नहीं है।

च.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

- 32. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात की गई टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि टिप्पणियां जो कि पुनरावृत्तियां हैं तथा जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात की जांच में उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है।
- 33. घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में, प्राधिकारी ने नोट किया कि एनआईपी और आयात मूल्य के बीच तुलना पर पिछले खंड में जांच की गई है, यह स्पष्ट है कि एमटीआर पीओआई बनाम मूल जांच पीओआई के लिए एनआईपी और आयात मूल्य की मात्रा में वृद्धि समान है और कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसके अलावा आयात और बिक्री दोनों के उत्पाद मिश्रण में दिखाई देने वाली कुछ गतिशीलता समीक्षा की मांग नहीं करती है। एनआईपी के मानकीकरण और निर्धारण से संबंधित आधारों के संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि यह प्राधिकरण के नियमों और सुसंगत अभ्यास के अनुरूप है।

34. इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के पश्चात टिप्पणियों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी दोहराते हैं कि आवेदकों को परिस्थितियों में इस सीमा तक परिवर्तन स्थापित करना आवश्यक था कि जिस आधार पर शुल्क लगाया गया था, वह इतना भौतिक रूप से बदल गया है कि यदि लागू एंटी-डंपिंग शुल्क हटा दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या फिर से होने की संभावना नहीं है। वर्तमान जांच में सभी इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के आलोक में, तथा वर्तमान जांच के दौरान रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्थापित तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में पहचाने गए आधार मौजूद नहीं हैं।

छ. निष्कर्ष और सिफारिश

35. प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरणों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा परिवर्तित परिस्थितियों के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

- i. वर्तमान जांच में विचारित उत्पाद दायरा और पीसीएन कार्यप्रणाली वही है जो मूल जांच में परिभाषित की गई थी।
- ii. विषयगत वस्तुओं के लिए 8 अंकों के स्तर पर कोई समर्पित कोड नहीं है तथा इन्हें विभिन्न एचएसएन कोडों के अंतर्गत आयात किया जा रहा है, जो इस जांच के दायरे में आते हैं।
- iii. आवेदक नियम 2(बी) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।
- iv. वर्तमान जांच का दायरा नियम 23(1ए) के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा परिवर्तित परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की गई है।

36. प्राधिकरण ने नोट किया कि मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को विचाराधीन उत्पाद के पहलू, परिस्थितियों में बदलाव और मार्जिन के पुनः परिमाणीकरण की आवश्यकता पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए

पर्याप्त अवसर दिया गया था। एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि थार्फलैंड में उत्पादकों पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क के पुनः परिमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

37. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण यह सिफारिश करना उचित समझते हैं कि अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 सितंबर 2021 के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क जारी रहेगा।

ज. आगे की प्रक्रिया

38. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 26th March, 2025

Case No. AD (MTR)-01/2024

Subject: Final Findings of Mid Term Review of anti-dumping duty imposed on the imports of "Aluminium Foil below 80 Microns" originating in or exported from Thailand

F. No. 7/3/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") received an application, on behalf of M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel and Power Ltd., M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., M/s GLS Foils Products Pvt. Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicants" or the "domestic industry") requesting initiation of a mid-term review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Aluminium Foil below 80 microns (hereinafter also referred to as the "subject goods" or the "product under consideration") to examine the need to re-evaluate and enhance the antidumping duty levied against imports of the subject goods originating in or exported from Thailand (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. An anti-dumping investigation with respect to Aluminium Foil below 80 micron originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia was initiated on 20th June 2020 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry. The Authority vide its Final Findings No. 6/21/2020-DGTR, dated 18th June 2021 recommended imposition of definitive anti-dumping duties, which were given effect vide Customs Notification No. 51/2021-Customs (ADD), dated 16th September 2021 for a period of five years.
3. The present mid-term review was initiated in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23(1A) of the Rules. The Authority is required to review, based on a duly substantiated request made for or on behalf of any interested parties, as to whether the change in circumstances warrant the modification of the existing anti-dumping duty.
4. In view of the duly substantiated application with *prima facie* evidence and in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/3/2024-DGTR dated 29th March 2024.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

- a. The Authority vide Notification No. 7/3/2024-DGTR dated 29th March 2024, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a mid-term review investigation concerning anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods from the subject country.
- b. The Authority sent a copy of the public notice to the Embassy of Thailand in India, known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
- c. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of Thailand, through its Embassy and to other interested parties who made a request in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- d. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the mid-term review investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file a response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit (including the extended time limit), as prescribed in the initiation notification, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
- e. The Authority forwarded copies of the notification and non-confidential version of the petition to the known producers/ exporters.
- f. The Government of Thailand, through its Embassy in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy of Thailand along with the details of the known producers/ exporters from Thailand in accordance with the Rule 6(5) of the Rules.
- g. In response to the above notification, the following producers/exporters from the subject country have filed response to the exporters' questionnaire:
 - i. Thai Ding Li New Materials Co. Limited, Rayong, Thailand
 - ii. Dingsheng New Materials Co. Limited, Rayong, Thailand
 - iii. Loften (Thailand) Co., Ltd.
- h. The Authority forwarded a copy of the notification and questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Caprihans India Ltd.
 - ii. Asawa Insulations Pvt Ltd
 - iii. Eminent Trade and Export Pvt. Ltd.
 - iv. Dalfo Flexicap Pvt. Ltd.

- v. Dalfo Flexicap Pvt. Ltd.
- vi. Silver Foils Pvt. Ltd.
- vii. Rockdude Impex Pvt. Ltd
- viii. Nagreeka Indcon Products (P) Ltd.
- ix. Suvjay Industries India LLP
- x. Ram Kishore Nagarmal Marketing Pvt. Ltd.
- xi. Jil Pack

- i. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 – 30th September 2023 (12 months).
- j. Transaction-wise import data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG, Systems. The Authority has relied upon the data of DG Systems for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the exporters.
- k. Further information was sought from the Applicants and responding exporters/importers to the extent deemed necessary.
- l. All the interested parties were requested to e-mail non-confidential versions of their submissions/responses/comments filed by them to all the other interested parties.
- m. The non-injurious price (hereinafter referred to as "NIP") has been determined based on the optimum cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the antidumping Rules. Such non-injurious price has been worked out so as to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th October 2024. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally on 16th October 2024, followed by rejoinder submissions, if any, on 23rd October 2024. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- o. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this notification.
- p. The Authority, during the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this notification, to the extent possible, and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- q. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever

possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- r. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this disclosure statement based on the facts available in accordance with the Rule 6(8) of the Rules.
- s. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 20th March 2025 and the interested parties were allowed time up to 5 PM on 25th March 2025 to comment on the same. The comments on disclosure statements received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- t. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = 83.21

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The product under consideration in the original investigation was:

“18. Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)” excluding the following:

- i. *Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.*
- ii. *Alu-Alu Laminate*
- iii. *Ultra-Light Gauge Converted*
- iv. *Aluminium Foil Composite*
- v. *Aluminium foil for capacitors width below 500 mm*
- vi. *Etched or formed Aluminium Foils*
- vii. *Aluminium composite panel*
- viii. *Clad with compatible non clad Aluminium Foil*
- ix. *Aluminium Foil for beer bottle*
- x. *Aluminium- Manganese- Silicon based and,/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad*
- xi. *Adhesive tapes*
- xii. *Colour coated aluminium foil*

19. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry are comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The

Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration, in accordance with the AD Rules.”

C.1. Views of the domestic industry

7. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

- i. The subject good in the present investigation is “Aluminium foil below 80 microns”.
- ii. The product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

C.2. Views of the other interested parties

8. The following are the submissions made by the other interested parties with regard to product under consideration and like article:

- i. Polyurethane Coted Aluminium Foil-either one side or both side, irrespective of colour, shape or coating should be excluded as no Indian producer is supplying the same.

C.3. Examination by the Authority

9. The product under consideration as held in the final findings of the original investigation, is as below:

“7. The product under consideration as noted in the initiation notification is “Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packaging materials of a thickness of 80 microns and below (with permissible tolerances)” excluding the following:

- i. *Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.*
- ii. *Alu Alu Laminate- Alu Alu Laminate of 40-50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.*
- iii. *Ultra-Light Gauge Converted- Ultra Light Gauge Converted is an Aluminium foil having thickness of 5.5 6 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.*
- iv. *Aluminium Foil Composite- Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.*

- v. *Aluminium foil for capacitors width below 500 mm- Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5-micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.*
- vi. *Etched or formed Aluminium Foils- Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.*
- vii. *Aluminium composite panel- Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in façade cladding and signage.*
- viii. *Clad with compatible non clad Aluminium Foil- Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.*
- ix. *Aluminium Foil for beer bottle- Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.*
- x. *Aluminium- Manganese- Silicon based and/or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.*

15. The Authority considered the exclusion requests of the interested parties. The opposing interested parties have requested for the following exclusions and the Authority has examined all the exclusion request hereinunder:

- i. *Battery Foil*
- ii. *Aluminium Foil below 5.5 micron*
- iii. *House foil and SRC foil*
- iv. *Adhesive tapes*
- v. *Color coated Aluminium foil*

i. *Battery foils- As regards exclusion of battery foil, it is noted that the interested parties have claimed that battery foil is a specialised kind of foil and the domestic industry is unable to manufacture battery foil in the desired specification. However, the domestic industry has submitted documentary evidence to show production and sale of battery foil. Hindalco has submitted that its Battery foil has been tested & qualified against highest standards of foil performance. Hindalco is manufacturing Aluminium battery*

foils in India and actively partnering LiB manufacturing revolution for EVs/various other applications.

A producer/exporter which has not exported the subject goods to India during the POI has sought exclusion of battery foils for Lithium-Ion batteries used in manufacturing of batteries for electric vehicles. The producer agrees that presently there is no production of electric vehicle batteries in India. Consequently, there was no demand for such battery foils in India during POI. The domestic industry has submitted invoices of their sales of such battery foils to BHEL which utilised in space applications having a higher technical threshold. This establishes the capability of the domestic industry to manufacture the product in case of demand. Therefore, the Authority does not exclude such a product from the scope of PUC.

ii. Aluminium foil below 5.5 micron- As regards the exclusion of Aluminium foil below 5.5 microns, it is seen that Jindal India had started manufacturing Aluminium foil below 5.5 micron since 2019 and they sold their first commercial quantity in December 2019. Jindal has also submitted various invoices indicating the total commercial quantity sold during the period of investigation. As regards the fact that Hindalco and Raviraj are not producing ULG below 5.5 micron, it is seen that it is not necessary that each and every constituents of the domestic industry should produce and supply each and every type of product. In fact, in a situation where a large number of producers are producing and selling a product which has large number of product types, it is quite natural that every producer tends to focus on some product types and none of the producers could wish to produce entirety of the product range. Thus, where the domestic industry is already manufacturing a type of subject goods, that cannot be excluded from the scope of product under investigation. Accordingly, the request for exclusion of Aluminium foil below 5.5 micron cannot be accepted.

iii. SRC and House foil- As regards exclusion of SRC and House foil, it is noted that the product types are imported into India and the domestic industry is producing and supplying the like article to these product type. In fact, SRC and house foil is being manufactured by all three petitioning companies and they have submitted invoices to substantiate the same. The other interested parties have not given any legal or factual basis for justifying exclusion of these two types of foil from the product scope. The opposing interested parties have contended that since the domestic industry is not producing these types in sufficient quantities and are not focussed on producing these types, it should be excluded from the product scope. It is seen that the opposing interested parties have not submitted any evidence on record to show that the domestic industry is not capable of producing these types of subject goods and is not selling in the domestic market. It is seen that the domestic industry is capable of producing these types of aluminium foil and also supplying these types to the domestic market. Further, in any case, it is noted that this kind of product type is produced and supplied by more than one producer. In case possible demand supply gap does not justify exclusion of particular product type.

iv. *Aluminium Foil Adhesive Tape- As regards exclusion of adhesive tapes, the domestic industry has contended that they are capable of producing this type but not producing the same at present. It is noted that since adhesive tapes are not being produced by the domestic industry at present and there was no production of the same in the POI as well, the same can be excluded from the product scope. Post the issuance of disclosure statement, certain interested party have requested that the adhesive tape be appropriately redefined. Accordingly, Adhesive tape is defined as “Adhesive tape is Aluminium foil (<80 mic) single side or both sides coated with adhesive for use as tape”.*

V. *Color coated aluminium foil- As regards exclusion of color coated aluminium foil, the same was excluded in the previous investigation on the ground that the domestic industry is not manufacturing the same. Since the fact remains same for the present investigation also, color coated aluminium foil to be excluded from the product scope. Color coated Aluminium foil is defined as “aluminium foil with either PE (polyester) coating of PVDF (fluorine Carbon), coating falling under CTH 7607”.*

18. *In view of the foregoing, para 7 and 15 the scope of product under consideration for the purpose of present investigation is as follows as read with para 7 and 15:*

“Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances) ” excluding the following:

- i. *Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.*
- ii. *Alu Alu Laminate*
- iii. *Ultra Light Gauge Converted*
- iv. *Aluminium Foil Composite*
- v. *Aluminium foil for capacitors width below 500 mm*
- vi. *Etched or formed Aluminium Foils*
- vii. *Aluminium composite panel*
- viii. *Clad with compatible non clad Aluminium Foil*
- ix. *Aluminium Foil for beer bottle*
- x. *Aluminium- Manganese- Silicon based and/or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad*
- xi. *Adhesive tapes*
- xii. *Color coated aluminium foil”*

10. The finding issued by the Authority on 18th June 2021 vide Notification No. 6/21/2020-DGTR recommended anti-dumping duty on “aluminium foil 80 microns and below” with the exclusions as mentioned above. The duty was imposed vide customs notification no. 51/2021-Customs (ADD) dated 16th September 2021.

11. The Authority conducted a parallel investigation on imports of Aluminium Foil below 80 micron from China PR wherein duties have been recommended vide Notification No. 06/35/2023 dated 20th March 2025. The said investigation covers only China PR and in respect of such product as are not subjected to ADD at present, whereas the present review investigation concerns only Thailand.
12. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act. Imports of the subject goods are entering into India under the following codes 76071 190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 and 76071992. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
13. The Authority had used PCNs in the previously conducted investigation and the same are being followed for the purpose of the present investigation.
14. It is noted that there are no significant differences in the article produced by the domestic industry and those exported from Thailand. The article produced by the domestic industry and that imported from Thailand are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the domestic industry are technically and commercially substitutable. It is observed that the consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the domestic industry interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product being imported from Thailand.

D. Domestic Industry and Standing

D.1. Views of the other interested parties

15. No submissions have been made by the other interested parties with regard to domestic industry and its standing.

D.2. Views of the domestic industry

16. The Applicants have made the following submissions with regard to the domestic industry and its standing:
 - i. The application has been filed by M/s. Hindalco Industries Ltd., Ms Shyam Sel & Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s. Ravi Raj Foils Ltd., M/s. GLS Foils Product Pvt. Ltd., and M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd.
 - ii. Other domestic producers namely, ESS DEE Aluminium Ltd., Sparsh Industries Pvt. Ltd., SRF Altech Ltd., and Trefoil Packaging Pvt. Ltd. have communicated their support to the application filed.

- iii. The Applicant companies have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer in India or producer/exporter from the subject country.
- iv. The Applicants' production constitutes a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

18. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel and Power Ltd., M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., M/s GLS Foils Products Pvt. Ltd. and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. It is noted that the applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any producers/exporters or importers of the subject goods from subject country. Therefore, the Authority holds that the applicants constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. It is further noted that the production by the applicants account for a major proportion in total Indian production. The application thus, satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the ADD Rules.

E. Scope of Mid Term Review and Changed Circumstances

E.1. Submissions made by other interested parties

19. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of present review:

- i. Initiation of the present review investigation is contrary to the provisions of Rule 23(1A) and is unnecessary. The MTR cannot be initiated for increasing ADD. The provisions of Rule 23(1A) state that MTR can be initiated only to review the need for continuation of duty.
- ii. The present investigation should be terminated without re-examination of quantum of ADD.
- iii. The Authority can only recommend complete or partial withdrawal of duty if it is evidenced that injury to the domestic industry is not likely to continue. There is no express provision enabling the Authority to initiate MTR for examining the need for increase in ADD.

- iv. Domestic industry should be aware that application for initiation of mid-term review cannot be filed by domestic industry under Rule 23(1A) for requesting increase in anti-dumping duty and therefore it requested initiation of anti-absorption review.
- v. The MTR is unnecessary as significant time has lapsed since the imposition of the original ADD. Considering the timelines, it will be short lived and only for a period of about 1 year. The original ADD is scheduled to expire in September 2026.
- vi. The domestic industry has also stated that the product profile of exports to India has changed in the present POI because of product types. It is not clear as to how this data has been obtained and even if correct, there is barely any change in the POI.
- vii. There is no positive information in the petition warranting the MTR under rule 23(1A). There is no evidence supporting the contentions that the Thai producers have not raised their export prices despite an increase in cost.

E.2. Submissions of the domestic industry

20. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of review:

- i. There is a need for re-evaluation of dumping margin and injury margin for exporters/producers in Thailand.
- ii. There is shift in the product profile exported by the exporters between the previous investigation and the present investigation.
- iii. There is an increase in costs of raw materials which is not reflected in export price.
- iv. There is an increase in dumping margin due to change in normal value without proportionate change in export price.
- v. The injury margin has also increased as a result of change in NIP.
- vi. The changed circumstances warrant a review as there has been a change in the product profile. Imports of products having higher dumping margin and injury margin has increased – both in absolute terms as also in relation to total imports into India.
- vii. There has been a change in the landed prices of imports. There has been an increase in the raw material prices and costs. The export price has also increased. When seen at the PCN level, export price has not increased in a commensurate manner as there has been an increase in the cost of production. The NIP has also increased due to increase in input costs. The same has also resulted in increased injury margins and dumping margins. Further, the imports have also increased significantly in the POI.
- viii. The provisions of law clearly and plainly state that the DA can initiate the review upon request by any interested party. The respondent has resorted to a selective reading of only sub-rule (1A) of Rule 23, without having reference to its other provisions. The reading of the provisions clearly suggest that the authority is not restricted to withdrawing the duty or revising it downwards. The Authority is empowered to enhance duties in a mid-term review.

- ix. The other interested parties have overlooked that the provision allows the Authority to initiate a review upon the request of any "interested party", which includes a producer of the like article in India as per Rule 2(c). Hence, the current application for a mid-term review by the domestic industry is maintainable.
- x. A plain reading of Rule 23(1A) does not suggest that the Authority is restricted to only withdrawing the duty or revising it downwards.
- xi. Rule 23(1A) mandates that the Authority must initiate a review upon request from any interested party who provides information substantiating the need. Additionally, it confirms that the Authority can remove the anti-dumping duty before the expiry of the five-year term if the mid-term review determines no further requirement for the levy.
- xii. The word "varied", which allows the Authority to revise the anti-dumping duty, is not limited to suggesting it can only be varied downward.
- xiii. The Domestic Industry asserts that Rule 23 should be read as a whole to understand the scope of sub-rule (1A), and that sub-rules (1) and (3) inform the application of sub-rule (1A).
- xiv. Rule 23(1) outlines the general principles for anti-dumping reviews, stating that anti-dumping duties remain in force as long as necessary to counteract injurious dumping. The phrase "to the extent necessary" acknowledges the Authority's power to re-evaluate the quantum of anti-dumping duties in review investigations under Rule 23(1A) and (1B). Rule 23(1) aligns with Article 11.1 of the Anti-Dumping Agreement.
- xv. In the Panel Report of US-DRAMs, the Panel observed that Article 11.1 contains a general necessity requirement, stating that anti-dumping duties remain in force only as long as necessary to counteract injurious dumping. Article 11.2 specifies the application of this rule, requiring authorities to review the need for the continued imposition of the duty.
- xvi. In EC-Tube or Pipe Fittings the Panel noted that Article 11.1 mandates that anti-dumping duties remain in force only if necessary to counteract injurious dumping. This general, unambiguous requirement forms the basis for the review procedures in Articles 11.2 and 11.3.
- xvii. The Panel in US-Shrimp II (Vietnam) reiterated that Articles 11.2 and 11.3 implement the general necessity requirement of Article 11.1, with Article 11.2 addressing the extent and duration of duties imposed on individual producers/exporters, while Article 11.3 pertains to the measure's imposition on imports from another Member as a whole.
- xviii. In Pakistan-BOPP Film (UAE), the Panel explained that Article 11.1 provides that anti-dumping duties remain in force only as long as necessary to counteract injurious dumping. Article 11.1 establishes an overarching principle operationalized in the procedures for changed circumstances and sunset reviews in the rest of Article 11.
- xix. Article 11.2 operationalizes the principles of Article 11.1, which mandate that anti-dumping duties remain only as long as necessary to counteract injurious dumping, and modifications of duties can occur during a review.

xx. Rule 23(1A) is analogous to India's obligations under Article 11.2 and should be interpreted similarly. The Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports emphasized that statutes aligned with treaty obligations should be construed broadly for uniform application across signatory nations.

xxi. The application of Rule 23(1A) must align with Rule 23(1), as both authorize the levy of anti-dumping duty to counteract injurious dumping, with the duty varied as necessary, potentially resulting in a higher duty.

xxii. Rule 23(3) applies the provisions of Rules 10 and 17 to a mid-term review under Rule 23(1A), allowing the Authority to recommend duties necessary to remove injury to the domestic industry, considering the principles in Annexure III.

xxiii. In Fairdeal Polychem, the Delhi High Court held that by virtue of "mutatis mutandis" in Rule 23(3), Rule 17(1) applies to reviews with necessary changes, extending the six-month permissible extension.

xxiv. Since Rule 17 provisions apply to the investigation, the Authority can determine export price, normal value, and margin of dumping, recommending necessary duties to counteract injurious dumping.

xxv. The question of whether the Authority can enhance duties in a mid-term review has been addressed by CESTAT in Graur & Weil v. The Designated Authority, where it upheld the enhancement of duties following a mid-term review application by the domestic industry.

xxvi. The respondent contends that Rule 23(1A) does not explicitly state that a domestic producer can apply for enhanced anti-dumping duty, unlike the EU Anti-dumping Rules.

xxvii. The Domestic Industry argues that since Rule 23(1) and Rule 23(3) govern Rule 23(1A), no additional explicit statement is needed to confirm the power to enhance duties in a mid-term review.

xxviii. In previous arguments, it was claimed that Rule 23 and Section 9A(5) do not permit the Authority to enhance duties during sunset review investigations, which allow for extension of duties if cessation would likely lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

xxix. Despite the absence of explicit language, CESTAT in Thai Acrylic Fibres v. The Designated Authority held that the Authority has incidental and ancillary powers to enhance duties to make them effective against dumping.

xxx. Similar conclusions were reached in Shanghai Fortune Chemicals Co. Ltd. v. The Designated Authority, where CESTAT noted that the Designated Authority can recommend higher or lower anti-dumping duties during reviews to effectively counteract dumping.

xxxi. It is wrongly contended that the Authority could not have initiated a mid-term review under Rule 23(1A) due to specific provisions for anti-absorption investigations.

- xxxii. The Domestic Industry argues that the provision of a separate anti-absorption investigation does not limit the Authority's power to initiate a mid-term review under Rule 23(1A), given the requirements are met and a substantiated application is filed.
- xxxiii. The Domestic Industry further argues that Dingheng's reliance on the Rishiroop Polymers judgment is based on selective reading and asserts that the Supreme Court recognizes the Authority's duty to inquire into specific parameters.
- xxxiv. Past and current practices of the DGTR support the conduct of a mid-term review to modify and enhance duties, as evidenced by several final findings in various investigations.
- xxxv. Various cases illustrate the necessity to recommend modification and continuation of anti-dumping duties to counteract dumping and injury to the domestic industry.
- xxxvi. The Authority's decision to not initiate an anti-absorption review and instead initiate a mid-term review evidences that the authority determined mid-term review to be an apt action.
- xxxvii. The application filed fulfils both criteria required by the law of positive information and of reasonable period of time elapsing.
- xxxviii. Domestic industry obtained PCN wise data through market intelligence.
- xxxix. There has been a significant change in the product profile exported by the exporter after the imposition of duties.
- xl. The extent of dumping and injury margins applicable in the original investigation was on the basis of different share of different PCNs. Import volume of high cost PCNs have increased in the present investigation. The change in product profile directly affects the weighted average dumping margin and injury margin, as the degree of dumping and injury is different in different PCNs.

E.3. Examination by the Authority

21. The present investigation was initiated as per Rule 23(1 A), which, inter-alia, provides as follows:

“(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any antidumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.”

22. The Authority notes that the present review has been initiated based on change in circumstances alleged by the domestic industry. The present investigation at the first instance has taken up examination of whether there has been change in circumstances which justify the enhancement

of the quantum of anti-dumping duty. Only in case justifiable grounds are made, the case for redetermination of quantum of duties would arise. In their application, the domestic industry has alleged the following grounds for change in circumstances:

- a. There is significant shift in the product profile exported by the exporter to the Indian market.
- b. There is significant increase in raw material price and consequently costs, without proportionate increase in the export price.
- c. There is a significant change in Indian industry production profile.

a. Change in product profile of foreign producers

23. The table below shows the extent of change in product profile of imports. The Authority notes that the pattern of imports for various PCNs has undergone some change as compared to the original investigation. However 80% of exports, both in the original investigations and the POI of the MTR, are concentrated in three product types:- House Foil Bare, SRC Bare and ULG Bare. Thus while there is a change, the same cannot be said to be significant and structural in nature. It may be difficult to expect the exports or sales of different product types to mirror the shares as they prevailed during the period of investigation. As market forces are dynamic in nature, some changes are expected and need to be allowed. It is not forthcoming if there are factors of lasting nature which are driving the change in product mix. Considering the above, the Authority holds that the changes in product profile are neither significant nor proved to be of lasting nature.

Type of Foil	Imports Volume as per Original Investigation	Imports as per Present Investigation	Share	
	MT	MT	%	%
Alu Alu Stock Bare	83	1,860	0.50%	7.79%
House Foil Bare	3,900	5,364	23.31%	22.46%
LG Bare	1,401	2,525	8.37%	10.57%
LG Converted	18	25	0.11%	0.10%
MG Bare	617	409	3.69%	1.71%
MG Converted	1,184	8	7.08%	0.03%
SRC Bare	5,761	4,338	34.43%	18.17%
ULG Bare	3,767	9,352	22.52%	39.16%
House Foil Converted	-	0	0.00%	0.00%
Grand Total	16,731	23,882	100.00%	100.00%

b. Significant increase in raw materials cost

24. With regard to the submission that there has been a significant increase in raw material prices and costs, which should lead to an increase in export price, the Authority has analysed this data as applicable in the POI of the original investigation and the present POI. The table below shows such comparison.

Particulars (Weighted Average)	Unit	Original POI	Present POI	Increase
Raw Material Cost	Rs./MT	***	***	***
NIP	Rs	***	***	***

25. It is noted that from the above table that the weighted average raw material cost for the domestic industry has increased by Rs. *** and the Non injurious price as per Annexure-III of the Anti-Dumping Rules has increased by Rs. ***. Thus, the predominant reason for increase in cost of domestic industry can be attributed to change in the cost of raw material.

26. Further the variation with reference to the import price between the original POI and the MTR POI may be seen from the table below:-

Type of foil	Import Price Rs/MT		
	O.I	MTR	Change
Alu-Alu Stock Bare	2,15,506	3,25,854	1,10,348
Home Foil Bare	1,96,114	2,81,233	85,120
Light Gauge (LG) Bare	2,28,707	3,25,382	96,674
Medium Gauge (MG) Bare	1,95,838	3,56,246	1,60,408
Medium Gauge (MG) Converted	2,44,815	10,26,227	7,81,412
Semi Rigid Container (SRC) Bare	1,98,754	2,94,261	95,507
Ultra-Light Gauge Bare	2,27,301	3,61,066	1,33,765
Weighted average			1,10,946

27. As is evident from the table related to import price, the weighted average difference is Rs. ***/MT. From the comparison, it is evident that the increase in import price and the NIP are approximately the same. Thus the import prices and NIP have broadly moved in tandem. The material change in circumstances is not reflected in the inter-se changes between the NIP and the import price.

c. Significant change in Indian industry production profile

28. The Authority notes that the composition of production of Indian industry has some what changed in the MTR POI as compared to the POI of original investigation. The table below highlights the variation in the share of different product types being manufactured by the domestic industry. Particularly, the DI production share in Alu Alu bare stock and ultra-light gauge bare has increased. If this is compared with the import composition in table in para 24, the

same trend is visible. The imports have also increased significantly in these two product types. Thus both the DI production and the imports are mirroring the trend in sales of different types of the products.

Type of foil	Total		Share	
	O.I.	MTR	O.I.	MTR
Alu-Alu Stock Bare	***	***	***	***
Home Foil Bare	***	***	***	***
Light Gauge (LG) Bare	***	***	***	***
Light Gauge (LG) Converted	***	***	***	***
Medium Gauge (MG) Bare	***	***	***	***
Medium Gauge (MG) Converted	***	***	***	***
Semi Rigid Container (SRC) Bare	***	***	***	***
Ultra-Light Gauge Bare	***	***	***	***
House Foil Converted	***	***	***	***
Cigarette Foil	***	***	***	***
Semi Rigid Container (SRC) Converted	***	***	***	***
Capacitor Foil	***	***	***	***
Total	***	***	***	***

29. The Authority holds that the applicant is required to establish a change in circumstances to such an extent that the basis on which the duty was imposed has altered so materially that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the anti-dumping duty in force is removed or varied. In light of submissions made by all the interested parties in the present investigation, and considering the facts established during the course of the present investigation on the basis of information and positive evidence on record, the Authority concludes that the grounds identified as change in circumstances do not exist.

F. Post Disclosure Comments

F.1 Views of other interested parties

30. The following comments were submitted by the other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

- It is very evident that the applicants failed to bring on record any positive information to justify a review of existing anti-dumping duties on imports of subject goods from Thailand under Rule 23(1A) of the Rules. This must lead to the termination of the present investigation forthwith.
- Disclosure statement makes it very evident that the applicants could not demonstrate existence of any such ground to such degree to warrant a review of existing ADD.
- Para 23 of the disclosure shows that there has not been any substantial change in the product profile of exporters to India. Out of the 9 PCNs considered, there has been some increase in

import of ULG Bare and Alu Alu Stock Bare. But such increases in two of the PCNs is not sufficient to say that there has been a change in the product profile itself so as to vitiate the effectiveness of the existing ADD.

- iv. Import price and NIP have broadly moved in tandem. This observation disproves the contention that there is an increase in costs on account of raw materials which is not proportionately reflected in the increase in the export price. In any case, it has been contended by us that there has not been any increase in the raw material price during the POI.
- v. It is evident that the increase in volume has been visible for ULG Bare and Alu Alu Stock Bare even for the domestic industry like imports, showing that there has been an increase in demand for these product types which must be considered as a natural evolution in the consumption of these products and not any outcome of any product shift contemplated as alleged.
- vi. The basic premise of the present MTR is unfounded, reassessment of dumping and injury margin is not essential in this review and the disclosure is apt in not conducting any fresh assessment of dumping and injury margin
- vii. Facts as disclosed suggest that it is fair and just to conclude that the grounds identified as change in circumstances do not exist.
- viii. Respondent agrees with the observations of the Authority and requests Authority to confirm such observations and consequently terminate the present investigation.

F.2 Views of the Domestic Industry

- 31. The following comments have been submitted by the domestic industry on the essential facts disclosed by the Authority:
 - i. Increase in raw material price, led to increase in cost for DI, thereby increasing non-injurious price (NIP). Rise in NIP is much higher than export price (EP) and submissions have been made in this regard.
 - ii. The Authority found that increase in NIP and import price is approximately same, leading to concluding that there is no material change in circumstances. Applicant disputes this and has made further submissions.
 - iii. Authority noted that composition of production of Indian Industry has changed, with DI's production of Alu Alu bare stock and ultra-light gauge bare increasing. Import for said product has also increased.
 - iv. Applicant has provided DM and IM determined by DI based on market intelligence, including NIP and CNV. Comparing DM and IM with existing ADD clearly shows substantial increase in respective margins. Thus, change in circumstances is evident and disputes the observation that NIP and EP rose on similar level. Had it been the case, such substantial increase in DM and IM would not have happened.

- v. The increase in weighted average NIP is ***Rs./MT whereas the increase in weighted average import price is ***Rs./MT.
- vi. Despite decline in EP or increase in EP being disproportionately lower than increase in cost, if Authority continues with its proposed conclusion, it would disregard 'changed circumstances' and render the law infructuous.
- vii. Despite the factors in the present case meriting action as per the parameters identified for changes circumstance in the Application proforma, the proposed conclusion has not taken them into consideration.
- viii. There has been a patent change in Industry profile. During original investigation, it was made up of 16 producers, the number of producers has nearly doubled with change in product profile.
- ix. It would be seen that even when four products constitute about ***% of the total market, the composition within four products have very materially changed. Whereas Medium Gauge products were majority before, Ultra-Light Gauge products are majority at present.
- x. There has been a significant demand in ultra-light gauge with LSKB, GLS, SSPL and SVEL setting up plants majorly focusing on production of same.
- xi. There has been significant increase in cost of sales of DI in POI. However, import price has not increased proportionately.
- xii. The Authority had accepted the application on the *prima facie* ground of changed circumstances. No opportunity was given to DI to clarify or substantiate facts during the course of investigation.
- xiii. Rate in increase in imports from Thailand; decline in import price of Thai imports; circumvention by third countries all substantiate the lasting nature of changes.
- xiv. Analysis of filed EQRs additionally substantiate that they are export oriented with surplus capacities and is likely to increase their exports.
- xv. Imports increased from Thailand till POI wherein it declined. This is due to cessation of duties on China PR. DI has the capacity to meet Indian demand entirely.
- xvi. PCN wise import prices have been significantly below the selling prices of the domestic industry. Selling price declined in the POI while the cost of sales increased. Thus, there is significant depression.
- xvii. The NIP determined by the Designated Authority is low and will not adequately remedy illegal dumping.
- xviii. Normation in raw materials, utilities and capacity utilisation is unjustified since subject goods involves various PCNs, each requiring distinct raw material consumption, utility usage, and capacity utilization based on its product thickness.
- xix. Not considering utility costs of GLS, reported on actual basis, and instead using Ravi Raj Unit II's consumption factors for calculation of utility costs is not only inconsistent with the Rules but have also led to lower utility cost than any other domestic producer.

- xx. The Authority have erroneously included changes in WIP while normating raw material costs although WIP has fluctuated between positive and negative figures during injury period, with the latter still being included for normation.
- xxi. The Authority has unfairly disallowed indirect selling and distribution expenses, including marketing expenses and Branch/head office expenses. This is not as per the rules and have never been disallowed before.
- xxii. The cost of production for Raviraj has been erroneously normated by considering past capacity utilisation although decline in capacity utilisation is due to corresponding product and its needs. Decline in capacity utilization is not inefficient utilisation of production capacity.

F.3 Examination by the Authority

- 32. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that the comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity.
- 33. With reference to comments made by the domestic industry, the Authority notes that as examined in earlier section on comparison between NIP and Import price, it is clear that increase in quantum of NIP and Import price, for the MTR POI vis-à-vis original investigation POI, it is similar and there is no significant difference. Further certain dynamism reflected in product mix of both imports and sales does not warrant a review. With reference to the grounds related to normation and determination of NIP, it is noted that the same is in the line with the rules and consistent practice of the Authority.
- 34. After having examined the post disclosure comments made by the interested parties, the Authority reiterates the Applicants were required to establish a change in circumstances to such an extent that the basis on which the duty was imposed has altered so materially that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the anti-dumping duty in force is removed or varied. In light of submissions made by all the interested parties in the present investigation, and considering the facts established during the course of the present investigation on the basis of information and positive evidence on record, the Authority determines that the grounds identified as change in circumstances do not exist.

G. Conclusion and Recommendation

- 35. Based on the submissions made, information provided, and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of changed circumstances, the Authority concludes the following:
 - i. The product scope and the PCN methodology considered in the present investigation remains the same as defined in the original investigation.

- ii. The subject goods do not have a dedicated code at 8-digit level and is being imported under various HSN codes which are covered within the scope of this findings.
- iii. The applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- iv. The scope of the present investigation is governed by provisions Rule 23(1 A).
- v. Changed circumstances have not been established by the domestic industry.

36. The Authority notes that the Mid-Term Review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of product under consideration, change in circumstances and need for re-quantification of margins. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that there is no need for requantification of anti-dumping duty applicable to producers in Thailand.

37. In view of the foregoing, the Authority considers it appropriate to recommend that the anti-dumping duty as imposed vide Notification No. No. 51/2021-Customs (ADD), dated 16th September 2021 would continue.

H. FURTHER PROCEDURE

38. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

DARPAN JAIN, Designated Authority